

आयोजित किया गया:सभी विवाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने में सक्षम नहीं हैं-विवाद की प्रकृति के आधार पर मध्यस्थता से किसी विवाद का बहिष्कार व्यक्त या निहित हो सकता है, और किसी विवाद के पक्ष को केवल इस कारण से मध्यस्थता का सहारा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है कि यह अनुबंध में प्रदान किया गया है, जिसके लिए वह एक हस्ताक्षरकर्ता है-किसी विवाद की मध्यस्थता की जांच तब की जानी चाहिए जब एक पक्ष 259 के तहत निवारण चाहता है।

258

एसएमटी। एम. हेमलाथा देवी और ओआरएस बनामबी. उदयश्री 260

कल्याणकारी विधान, मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कल्याणकारी विधान का एक हिस्सा है-उपभोक्ता विवादों को विधायिका द्वारा सार्वजनिक मंचों को सार्वजनिक नीति के एक उपाय के रूप में सौंपा जाता है-इसलिए, आवश्यक निहितार्थ से ऐसे विवाद गैर-मध्यस्थता विवादों की श्रेणी में आते हैं, और इन विवादों को 'मध्यस्थता' जैसे निजी मंचों से दूर रखा जाना चाहिए, जब तक कि दोनों पक्ष स्वेच्छा से सार्वजनिक मंचों के समक्ष समाधान पर मध्यस्थता का विकल्प नहीं चुनते हैं-वर्तमान मामले में, आवेदन यू/एस।11, एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अपीलकर्ताओं के नेतृत्व में मध्यस्थता अधिनियम, 1996, जो इस स्थिति को बरकरार रखने वाले विवादित आदेश थे, बनाए रखने योग्य नहीं था-उच्च न्यायालय ने अपने दो विवादित आदेशों में सही दृष्टिकोण अपनाया, जहां उसने मामले में हस्तक्षेप करने और एक मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार कर दिया-एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम.आफताब सिंह [2018] 14 एस. सी. आर. 791 (एम्मार III) एस. पर समान रूप से लागू होगा।11 उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन-दोनों प्रावधान एस में शामिल हैं।8 और एस।11 [अर्थात्, क्रमशः उप-धारा (1) और उप-धारा 6 क], प्रतीत होता है कि संबंधित न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता या मध्यस्थ की नियुक्ति के संदर्भ में परीक्षा के दायरे को प्रतिबंधित करता है, जैसा भी मामला हो, और भाषा सामान्य होने के कारण, "किसी भी निर्णय, डिग्री या आदेश के बावजूद" दोनों न्यायालयों के समक्ष एक समान प्रश्न रखता है-अपील खारिज कर दी जाती है।[पैरा 9,22,23]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019-मध्यस्थता अधिनियम, 1996।11,8 - अपीलार्थियों की याचिका है कि चूंकि यह बिल्डर है जिसने पहली बार एक आवेदन के माध्यम से "अदालत" का दरवाजा खटखटाया था।11 मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए, समझौते के संदर्भ में, उपभोक्ता को उपभोक्ता मंच के समक्ष उपचार की मांग करने के बजाय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, जैसा कि पक्षों के बीच सहमति (उनके समझौते में) थी:

आयोजित किया गया:सवाल चुनाव या पसंद का है, न कि किस पक्ष ने पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया था-इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विवाद की प्रकृति होगी, जो

इसके निवारण के लिए मंच का निर्धारण करेगी-कानून उपभोक्ता को यह विकल्प देता है कि या तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कोई उपाय प्राप्त करें, न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज करें, या मध्यस्थता के लिए जाएं-यह विकल्प बिल्डर के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वे 2019 के अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' नहीं हैं-यह यहाँ प्रतिवादी है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किसी उपाय का लाभ उठा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

निजी मंच यानी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने या उपभोक्ता मंच के समक्ष शिकायत करने के बीच एक "विकल्प" चुनना था, जो कि एक सार्वजनिक मंच है-उसने बाद वाले के पास जाने का फैसला किया-एस पर उच्च न्यायालय के समक्ष उसका जवाब।¹¹ बिल्डर का आवेदन मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए उनका निवेदन नहीं था-अपने जवाब में, उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष एक उपभोक्ता के रूप में अपने द्वारा की गई शिकायत के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित किया, जो एक 'न्यायिक प्राधिकरण' है और इसलिए एस।⁸ मध्यस्थता अधिनियम लागू होगा न कि एक आवेदन।¹¹ मध्यस्थता अधिनियम-केवल इसलिए कि बिल्डर ने पहले न्यायालय (यू/एस. 11, मध्यस्थता अधिनियम, 1996) का दरवाजा खटखटाया था, स्वयं उपभोक्ता न्यायालयों की अधिकारिता को समाप्त नहीं करेगा-किसी न्यायालय की अधिकारिता सबसे तेजी से पहले न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है, बल्कि विवाद की प्रकृति, मामले में सार्वजनिक नीति, विधायिका की इच्छा, विभिन्न कारकों के बीच उपभोक्ता का चुनाव या पसंद द्वारा निर्धारित की जाती है।[पैरा 10]

उपभोक्ता संरक्षण-मध्यस्थता अधिनियम, 1996 -एस. 11 (6 ए), 8 (1)-उपभोक्ता मंचों के समक्ष अपने समाधान का पीछा करने वाले उपभोक्ता के बारे में संदेह है कि वह मध्यस्थता के लिए जाने के खिलाफ है, हालांकि वह एक मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है, जो एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से समाप्त हो गया है।आफताब सिंह [2018] 14 एस. सी. आर. 791 (एम्मार III)-इसने उप-धारा 6 ए को एस. में शामिल करने के आलोक में इस मुद्दे की नए सिरे से जांच की।¹¹ और उप-धारा 1 से एस।⁸, मध्यस्थता अधिनियम, 1996-कानूनी स्थिति जो संशोधनों से पहले मौजूद थी और कानूनी स्थिति पर संशोधन के प्रभाव के रूप में जांच की गई, चर्चा की गई।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986-मध्यस्थता अधिनियम, 1996-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, एक विशेष और लाभकारी विधान-प्रदान किए गए उपचार विशेष उपचार हैं और एक उपभोक्ता को उनसे वंचित नहीं किया जा सकता है:

आयोजित किया गया:एक विशेष और लाभकारी कानून होने के नाते, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रदान किए गए उपाय विशेष उपाय हैं और एक उपभोक्ता को पार्टियों के बीच

मध्यस्थता समझौते के बावजूद, इस तरह के उपाय का लाभ उठाने का विकल्प चुनने पर उनसे वंचित नहीं किया जा सकता है-यह उपभोक्ता को प्रदान किया गया एक उपाय है जहां उपभोक्ता उसे प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं में से किसी में भी दोष देता है और इसलिए वह विधायिका द्वारा उसे प्रदान किए गए उपभोक्ता मंच के समक्ष अपनी शिकायतों का निवारण चाहता है।[पैरा 16] 261

एसएमटी। एम. हेमलाथा देवी और ओआरएस बनामबी. उदयश्री 262

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनामआफताब सिंह (2019) 12 एस. सी. सी. 751:
[2018] 14

एससीआर 791-पर निर्भर।

बूज एलन और हैमिल्टन इंक. बनामएस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड और
अन्य (2011) 5 एस. सी. सी. 532:[2011] 7 एस. सी. आर. 310; फेयर एयर
इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड बनामएन. के. मोदी (1996) 6 एससीसी 385:[1996] 4 पूरक।
एससीआर 820; राष्ट्रीय बीज

निगम लिमिटेड बनाम एम. मधुसूदन रेड्डी और एक अन्य (2012) 2 एससीसी 506:[2012]
2 एससीआर 1065; रोज़डेल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अघोर भट्टाचार्य और अन्य
(2018) 11 एससीसी 337; आफताब सिंह बनाम एम्मार एमजीएफ

लैंड लिमिटेड और ए. एन. आर., 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. डी. आर. सी.
1614; एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम आफताब सिंह, 2018 एस. सी. सी.
ऑनलाइन एस. सी. 2378; लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम. के. गुप्ता (1994) 1
एस. सी. सी. 243:[1993] 3 पूरक।एससीआर 615;

सचिव, थिरुमुरुगन सहकारी कृषि ऋण समिति बनाम एम.

ललिता (2004) 1 एस. सी. सी. 305:[2003] 6 पूरक।एस. सी. आर. 659; स्काइपैक
कोरियर्स लिमिटेड बनाम.टाटा केमिकल्स लिमिटेड, (2000) 5 एस. सी. सी.[2000] 1
पूरक।एससीआर 324;

ए. अय्यासामी बनाम ए. परमशिवम और अन्य (2016) 10 एससीसी 386:[2016] 11
एस. सी. आर. 521; अमित लालचंद शाह बनाम ऋषभ एंटरप्राइजेज, (2018) 15 एस. सी.
सी. 678:[2018] 6 एस. सी. आर. 1001; एस. बी. पी. एंड कंपनी बनामपटेल एंग।

लिमिटेड (2005) 8 एससीसी 618:[2005] 4 पूरक।एस. सी. आर. 688; विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कार्पोरेशन।(2021) 2

एससीसी 1:[2020] 11 एस. सी. आर. 1001-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील संख्या 6500-6501।

हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के 2020 के ए. आर. बी. ए. No.97 में दिनांकित 19.05.2022 और 2022 के आर. आई. ए. No.01 में दिनांकित 25.11.2022 से।

रूप:

किशोर राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, हिमिंदर लाल, रॉय अब्राहम, सुश्री रीना रॉय, अखिल अब्राहम, सुश्री नीलम सैनी, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

कृष्ण देव जगरलामुदी, सुश्री भाबना दास, सुश्री इंदरदीप कौर रैना, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, जे।

छुट्टी दे दी गई।

2. इस अदालत के समक्ष अपीलकर्ताओं ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के दो आदेशों को चुनौती दी है।प्रथम आदेश दिनांक 1 का आदेश है, जिसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'मध्यस्थता अधिनियम, 1996') की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अपीलकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।उच्च न्यायालय द्वारा इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि विवाद एक न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित था, जो कि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच (संक्षेप में 'जिला उपभोक्ता मंच') है, जहां एक शिकायत समझौते के दूसरे पक्ष के नेतृत्व में की गई है, जो एक उपभोक्ता है और इसलिए अपीलकर्ताओं के पास मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत मध्यस्थता से पहले संदर्भ के लिए एक आवेदन दायर करने का विकल्प है।नतीजतन, अपीलकर्ताओं ने विवाद को मध्यस्थता के लिए

संदर्भित करने के लिए एक आवेदन दायर किया। जिला उपभोक्ता मंच ने इस आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता ने उपभोक्ताओं के लिए एक लाभकारी कानून, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (जिसे इसके बाद '2019 अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत "न्यायिक प्राधिकरण" के समक्ष एक सार्वजनिक कानून उपचार का आह्वान किया है और इसलिए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, विवाद गैर-मध्यस्थ है। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत उनके आवेदन को खारिज करने के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष उसके पहले के आदेश दिनांक 19.05.2022 की समीक्षा के लिए एक समीक्षा आवेदन का नेतृत्व किया। इस समीक्षा आवेदन को उच्च न्यायालय के दिनांक 25.11.2022 के दूसरे आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, (जिसे इस न्यायालय के समक्ष फिर से विवादित किया गया है), इस आधार पर कि अपीलकर्ताओं ने पहले ही दिनांकित 19.05.2022 के आदेश पर कार्रवाई की थी, और इसलिए अब दिनांकित 19.05.2022 के आदेश की समीक्षा की मांग करने से रोक दिया गया है। ये दोनों आदेश हैं जिन्हें इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

3. आज जो तथ्य सामने आए हैं, वे यह हैं कि उपभोक्ता (इस न्यायालय के समक्ष एकमात्र प्रतिवादी) के नेतृत्व में की गई शिकायत को जिला उपभोक्ता मंच और बिल्डरों (यानी इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं) द्वारा पहले ही अनुमति दे दी गई है, उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे निर्मित विला के साथ भूखंड का कब्जा सौंप दें और 1 लाख रुपये (263 रुपये) का मुआवजा दें।

एसएमटी। एम. हेमलाथा देवी और ओआरएस बनाम बी. उदयश्री [सुधांशु धूलिया, जे.] 264 केवल पंद्रह लाख) और डिफॉल्ट शर्त के साथ रु. 1,00,000-(केवल एक लाख रुपये) की लागत। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा दिए गए निर्णय से उन कारणों का पता चलता है कि बिल्डर अपने वादे से क्यों पीछे हट गया और चूक क्यों की:

“....., विरोधी पक्ष सं। 3 ने समाप्ति नोटिस भेजने का विकल्प चुना था और यह जानते हुए रद्द विलेख के निष्पादन की मांग की थी कि समझौते की तारीख से भूखंड का मूल्य 10 गुना से अधिक हो गया है और विरोधी पक्ष मूल्य मूल्य में इस तरह की वृद्धि का लाभ उठाना चाहते हैं। विरोधी पक्ष नं। 3 ने अपने दायित्व के निष्पादन के लिए कोई उचित समय नहीं दिया, हालांकि कब्जा सौंपने के लिए समय पर विरोधी पक्ष सं। 3 बिक्री के समझौते में। विरोधी पक्ष नं। 3 ने वर्ष 2020 में समाप्ति नोटिस जारी किया था, हालांकि वह मार्च, 2017 तक विला का कब्जा सौंपने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहे।

विकासकर्ता की विफलता, जो वर्तमान मामले में भूमि का मालिक भी है, संविदात्मक रूप से निर्धारित समय के भीतर शिकायतकर्ता-खरीदार को आवासीय संपत्ति का कब्जा सौंपने में विफलता को अवज्ञा के रूप में माना जाता है। विरोधी पक्षों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के संबंध में अनुबंध के कार्यान्वयन में निष्पादित की जाने वाली कार्रवाई की प्रकृति और तरीके में

त्रुटि, कमी या अपर्याप्तता मौजूद है। बिक्री समझौते की शर्तों का मसौदा डेवलपर के हित को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है (विरोधी पक्ष सं.3)। ऐसी व्यापार प्रथा जो प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा, मूल्य में हेरफेर या उसके वितरण की शर्तों को लाती है या वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित बाजार में आपूर्ति को इस तरह से लागू करती है कि उपभोक्ता पर अनुचित लागत या प्रतिबंध लगाए जाएं और इसमें ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति में या ऐसी सेवाएं प्रदान करने में व्यापारी द्वारा सहमत अवधि से आगे की देरी शामिल होगी जिसके कारण या जिसके कारण मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है, विरोधी पक्षों द्वारा प्रतिबंधात्मक प्रथा के अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा, विरोधी पक्षों का कार्य सेवा की योग्यता और अनुचित व्यापार व्यवहार की अवहेलना के बराबर है। अतः, शिकायतकर्ता के पक्ष में बिंदु संख्या ए का उत्तर दिया जाता है।

10. बिंदु संख्या बी:

घर खरीदार अपनी मेहनत की कमाई को अचल संपत्ति परियोजनाओं में इस उम्मीद के साथ लगाते हैं कि वे एक दिन अपने सपनों के घर के मालिक होंगे। हालांकि,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब बिल्डर लंबे समय की देरी के बाद भी अपने घरों का कब्जा देने में विफल रहते हैं।

वर्तमान मामले में, विरोधी पक्ष का दायित्व सं. 3 (जो भूमि का स्वामी और विकासकर्ता है) बिक्री के समझौते में उल्लिखित समय पर विला को वितरित करने के लिए उक्त समझौते के अनुसार राशि के भुगतान की प्राप्ति के बावजूद पूरा नहीं किया गया था। विला के निर्माण के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन किए बिना विरोधी पक्षों द्वारा भूखंड के हस्तांतरण के लिए आंशिक भुगतान की प्राप्ति और इस बहाने से एकतरफा रूप से बिक्री के समझौते को रद्द करना कि विषय संपत्ति के लिए कीमतें बढ़ गई हैं, सेवा की अवज्ञा करने और विरोधी पक्षों की ओर से अनुचित व्यापार प्रथा को अपनाने के अलावा और कुछ नहीं है।”

बिल्डर, जो इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता हैं, पहले ही राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष अपनी वैधानिक अपील दायर कर चुके हैं जो वर्तमान में लंबित है और जिला मंच के आदेश पर रोक लगा दी गई है।

4. इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों का आवश्यक तर्क यह है कि उच्च न्यायालय ने धारा 11 (उप-धारा 5 और उप-धारा 5) के तहत अपीलार्थियों के आवेदन को खारिज करने में एक बड़ी त्रुटि की है। 6) मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के इन कारणों से कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 11 के संशोधित प्रावधान के तहत, यानी 2016 में एक संशोधन के माध्यम से धारा 11 में उप-धारा 6 ए को शामिल करने के बाद, उच्च न्यायालय के पास मामले को

मध्यस्थता के लिए भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिस प्रावधान को सेवा में लगाया गया है, वह इस प्रकार है:

“11. मध्यस्थों की नियुक्ति:- XXX

XXX

XXX

6 क) उच्चतम न्यायालय या, यथास्थिति, उच्च न्यायालय, उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, किसी भी निर्णय के बावजूद, डिक्री या

1 यह ध्यान रखना आवश्यक हो सकता है कि उपरोक्त प्रावधान 2016 के एक अधिनियम संख्या 3 द्वारा जोड़ा गया था और हालांकि 2019 के एक अधिनियम No.33 द्वारा, उप धारा 6A को हटा दिया गया है, लेकिन चूंकि संशोधन अधिनियम (2019 के No.33) के प्रासंगिक प्रावधानों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए उप धारा 6A अभी भी लागू है।

265

एसएमटी। एम. हेमलाथा देवी और ओआरएस बनामबी. उदयश्री [सुधांशु धूलिया, जे.] 266

किसी भी न्यायालय का आदेश, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच के लिए नहीं है।”

5. इसलिए, हमारे समक्ष आक्षेपित दो आदेशों की वैधता की जांच मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 11 और धारा 8 की उप-धारा 6 ए के आलोक में की जानी चाहिए। इस प्रकार हम इस बात की भी जांच करेंगे कि क्या पक्षों के बीच विवाद मध्यस्थता योग्य है, और एक बार जब कोई पक्ष एक विशेष लाभकारी कानून के तहत एक सार्वजनिक मंच के समक्ष उपचार का लाभ उठा लेता है, तो क्या उसे मध्यस्थता के लिए जाने के लिए मजबूर किया जा सकता है?

किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, हमें पहले पक्षों के बीच विवाद की प्रकृति का उल्लेख करना होगा। इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी एक घर खरीदार है जिसने 27.08.2013 पर वर्तमान अपीलार्थियों के साथ बिक्री के लिए समझौता किया था। वर्तमान अपीलार्थियों को इसके बाद बिल्डरों/मालिकों और उत्तरदाताओं को खरीदार/उपभोक्ता के रूप में संदर्भित किया जाएगा। बिल्डरों/मालिकों की संख्या तीन है। वे इस प्रकार हैं: (क) मेसर्स आर. जी. प्राइम स्पेस प्राइवेट लिमिटेड

(ख) श्रीमती। एम. हेमलता देवी

(ग) मेसर्स लीजेंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड

वे उस भूमि के संयुक्त मालिक हैं जिस पर वे खरीदार/उपभोक्ता श्रीमती के लिए एक आवासीय घर/विला बनाने के लिए सहमत हुए थे। बी. उदयश्री। 27.08.2013 दिनांकित समझौते की शर्तों में कहा गया है कि परियोजना मेसर्स लीजेंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की

जाएगी जो संपत्ति के मालिकों में से एक है। जिस भूमि पर आवासीय घर/विला का निर्माण किया जाना था, उसका कुल क्षेत्रफल 357 वर्ग किलोमीटर था। कोकापेट गाँव, राजेंद्र नगर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना में यार्ड और कुल निर्माण 4,000 वर्ग किलोमीटर था। 42,000/- (केवल उनतालीस लाख रुपये और बयालीस हजार रुपये) की कुल बिक्री के लिए।

6. समझौते के अनुसार, भुगतान का तरीका खंड 9.1, 9.2 और 9.3 के अनुसार किया जाना था जो निम्नानुसार है:

“ 9.1 मोड: खरीदार ने विकासकर्ता को निम्नलिखित तरीके से उपरोक्त खंड 8.1 में उल्लिखित कुल प्रतिफल का भुगतान किया:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

एस. नहीं। तिथि		chq. नहीं। बैंक		राशि
1	29/08/2013	303650	आईएनजी, वैश्य बैंक, हैदराबाद	4,94,200
			कुल	4,94,200

9.2 रुपये की शेष राशि। 44.47,800/- (केवल चालीस लाख सात हजार आठ सौ रुपये) का भुगतान विक्रेता द्वारा खरीदार या उसके नामितों के पक्ष में बिक्री विलेख के पंजीकरण के समय किया जाएगा। 9.3 सार: कुल प्रतिफल का समय पर भुगतान इस अनुबंध का सार है।”

घर का अधिकार खंड 10.1 और 10.1 के अनुसार दिया जाना था। 1 उस समझौते के बारे में जो इस प्रकार है:

“ 10.1 स्वामित्व: निर्मित विला के साथ उक्त भूखंड का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा डेवलपर द्वारा बिक्री विलेख और निर्माण समझौते में उल्लिखित कुल विचार के पूर्ण भुगतान के साथ-साथ खरीदार को दिया जाएगा और खरीददार के पक्ष में बिक्री विलेखों का पंजीकरण विला के पूरा होने के बाद किया जाएगा।

10.1.1 विकासकर्ता बिक्री के समझौते की तारीख से तीन साल और छह महीने की छूट अवधि के भीतर उक्त विला का कब्जा सौंपने के लिए सहमत होता है। यदि डेवलपर निर्धारित समय में विला का कब्जा सौंपने में असमर्थ है तो डेवलपर खरीदार को प्रति वर्ग मीटर 5/- रुपये का मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। फीट।, विला के निर्माण को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए प्रति माह।”

7. इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बिल्डरों/मालिकों को समझौते की तारीख से तीन साल के भीतर पूरी तरह से निर्मित घर/विला खरीदार को सौंपना था, यानी छह महीने की छूट अवधि के साथ। दूसरे शब्दों में, इस निर्मित घर/विला को 27 फरवरी, 2017 को या उससे पहले खरीदार/उपभोक्ता को सौंप दिया जाना था। जाहिर है कि ऐसा नहीं किया गया है। इसके बजाय जो हुआ वह यह है कि 2020 में, यानी उस तारीख से तीन साल बाद जब निर्मित घर/विला खरीदार को सौंपा जाना था, बिल्डर खरीदार को एक "समाप्ति सूचना" भेजता है और समझौते को समाप्त कर देता है, जाहिरा तौर पर इस आधार पर कि खरीदार ने "निर्माण समझौते" पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। यह विवादित नहीं है कि 267 पर हस्ताक्षर करने के समय

एसएमटी। एम. हेमलाथा देवी और ओआरएस बनाम बी. उदयश्री [सुधानशु धूलिया, जे.] 268

वर्ष 2013 में हुए समझौते में खरीदार ने समझौते के संदर्भ में (खंड 9.1, 9.2 और 9.3) 1 करोड़ रुपये की पहली किस्त सौंपी थी। 4,94,200-बिल्डरों/मालिकों को (केवल चार लाख 94 हजार दो सौ रुपये)। शेष राशि (47,800/- रुपये) का भुगतान बिक्री विलेख के पंजीकरण और निर्मित घर को खरीदार/उपभोक्ता को सौंपते समय किया जाना था। यह घटना, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कभी नहीं हुई।

8. इस बीच, बिल्डरों/मालिकों ने उपभोक्ता/खरीदार को नोटिस भेजने के बाद मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 11 की उप-धारा 5 और 6 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया।

खरीदार, जो एक उपभोक्ता भी था, ने 2019 के अधिनियम के तहत जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। उसी समय, धारा 11 आवेदन का नोटिस प्राप्त करने के बाद, प्रत्यर्थी ने न्यायालय के समक्ष अपना जवाब दिया। अपने उत्तर में, प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि एक उपभोक्ता होने के नाते उसने न्यायिक प्राधिकरण, जो कि जिला उपभोक्ता मंच है, के समक्ष एक शिकायत दायर की है, जहां मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत एक आवेदन हमेशा अपीलार्थियों के लिए उपलब्ध है। दिनांक 1 के विवादित आदेश के अनुसार, वर्तमान अपीलार्थियों के आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, और अपीलार्थियों को जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 8 के आवेदन को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता दी गई थी। यह आवेदन (मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत), जैसा कि हमने पहले ही ऊपर उल्लेख किया है, बाद में जिला उपभोक्ता मंच द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि विधायिका ने जानबूझकर 2019 के अधिनियम के तहत किसी अन्य उपाय के अलावा एक उपाय प्रदान किया था जो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध हो सकता है और हालांकि पक्षों के बीच एक मध्यस्थता खंड है, लेकिन यह स्वयं उपभोक्ता न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को इस कारण से नहीं हटाएगा कि यह एक सार्वजनिक मंच पर उपभोक्ता के लिए उपलब्ध एक उपाय है। जिला उपभोक्ता मंच ने भरोसा किया

एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय का निर्णय।आफताब सिंह,

(2019) 12 एस. सी. सी. 751 ("एम्मार III") (सर्वोच्च न्यायालय का यह मौलिक निर्णय, हम थोड़ी देर में विस्तार से चर्चा करेंगे), जिसमें यह कहा गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

अभिनिर्धारित किया कि समझौते में एक मध्यस्थता खंड शिकायत पर विचार करने के लिए उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं करता है। उनके धारा 8 के आवेदन को खारिज करने के बाद, अपीलकर्ताओं ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें इसके दिनांक 19.05.2022 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई। पुनरीक्षण याचिका को दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से इस आधार पर भी खारिज कर दिया गया था कि पहले के आदेश पर अपीलार्थियों द्वारा कार्रवाई की गई थी। 9. अब इस न्यायालय के समक्ष निर्णयों की एक लंबी कतार है, जिसमें वह निर्णय भी शामिल है जो धारा 8 की उप-धारा (1) में संशोधन के बाद आया था और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 11 में उप-धारा 6 ए को शामिल करने के बाद आया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 8 की उप-धारा (1) के बावजूद न्यायालय को न केवल यह पता लगाना है कि समझौते में मध्यस्थता खंड है या नहीं, बल्कि यह भी पता लगाना है कि विवाद मध्यस्थता योग्य है या नहीं।

2. सभी विवाद मध्यस्थता के लिए भेजे जाने में सक्षम नहीं हैं। कुछ विवादों की प्रकृति ऐसी हो सकती है कि उन्हें कभी भी मध्यस्थता मेज के पास नहीं भेजा जाना चाहिए। एक उदाहरण देने के लिए, कुछ प्रकार के आपराधिक मामले, सार्वजनिक भ्रष्टाचार से जुड़े मामले आदि होंगे। इस पक्ष पर इस न्यायालय द्वारा ब्रूज एलन और हैमिल्टन इंक में अच्छी तरह से विचार किया गया है।

v. एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड और अन्य, (2011) 5 एस. सी. सी. 532 और इसके पास है

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

“35. मध्यस्थ न्यायाधिकरण निजी मंच हैं जिन्हें विवाद के पक्षों द्वारा स्वेच्छा से चुना जाता है, ताकि वे देश के कानूनों के तहत गठित अदालतों और न्यायाधिकरणों के स्थान पर अपने विवादों का निर्णय ले सकें। प्रत्येक दीवानी या वाणिज्यिक विवाद, या तो संविदात्मक या गैर-संविदात्मक, जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, सैद्धांतिक रूप से मध्यस्थता द्वारा निर्णय लेने और हल करने में सक्षम है जब तक कि मध्यस्थ न्यायाधिकरणों की अधिकारिता को या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा बाहर नहीं रखा जाता है। कार्यवाहियों की कुछ श्रेणियों का निर्णय विधायिका द्वारा सार्वजनिक नीति के मामले में विशेष रूप से सार्वजनिक मंचों के लिए आरक्षित है। कुछ अन्य श्रेणियों के मामले, हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं

2 “सभी मामले मध्यस्थता के लिए भेजे जाने में सक्षम नहीं हैं। अंग्रेजी कानून के मामले के रूप में कुछ मामले केवल अदालत के लिए आरक्षित हैं और यदि कोई न्यायाधिकरण उनसे निपटने का इरादा रखता है तो परिणामी निर्णय अप्रवर्तनीय होगा। इनमें ऐसे मामले शामिल हैं जहां आवश्यक उपचार का प्रकार वह नहीं है जो एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को देने का अधिकार है।” [मध्यस्थता पर रसेल (22 संस्करण)] 269

एसएमटी। एम. हेमलाथा देवी और ओआरएस बनामबी. उदयश्री [सुधांशु धूलिया, जे.] 270

सार्वजनिक मंचों (न्यायालयों और न्यायाधिकरणों) द्वारा निर्णय के लिए आरक्षित, आवश्यक निहितार्थ से निजी मंचों के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। नतीजतन, जहां कारण/विवाद अविवेकी है, वह न्यायालय जहां एक मुकदमा लंबित है, अधिनियम की धारा 8 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर देगा, भले ही पक्षकार ऐसे विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता पर सहमत हुए हों।

36. गैर-मध्यस्थ विवादों के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त उदाहरण हैं: (i) उन अधिकारों और देनदारियों से संबंधित विवाद जो आपराधिक अपराधों को जन्म देते हैं या उत्पन्न होते हैं; (ii) तलाक, न्यायिक अलगाव, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, बाल अभिरक्षा से संबंधित वैवाहिक विवाद; (iii) संरक्षकता के मामले; (iv) दिवालिया और समापन के मामले; (v) वसीयती मामले (प्रोबेट का अनुदान, प्रशासन के पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र); और (vi) विशेष कानूनों द्वारा शासित बेदखली या किरायेदारी के मामले जहां किरायेदार को बेदखली के खिलाफ वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है और केवल विशिष्ट न्यायालयों को बेदखली देने या विवादों का फैसला करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है।”

मध्यस्थता से किसी विवाद का बहिष्कार स्पष्ट या निहित हो सकता है, जो फिर से विवाद की प्रकृति पर निर्भर करता है, और किसी विवाद के पक्ष को केवल इस कारण से मध्यस्थता का सहारा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है कि यह अनुबंध में प्रदान किया गया है, जिसके लिए वह एक हस्ताक्षरकर्ता है। किसी विवाद की मध्यस्थता की जांच तब की जानी चाहिए जब एक पक्ष मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद कल्याणकारी कानून के तहत निवारण चाहता है। ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम निश्चित रूप से उपभोक्ता के हितों की रक्षा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कल्याणकारी कानून का एक हिस्सा है। उपभोक्ता विवादों को विधायिका द्वारा सार्वजनिक नीति के एक उपाय के रूप में सार्वजनिक मंचों को सौंपा जाता है। इसलिए, आवश्यक निहितार्थ से ऐसे विवाद गैर-मध्यस्थता विवादों की श्रेणी में आएंगे, और इन विवादों को ‘मध्यस्थता’ जैसे निजी मंचों से दूर रखा जाना चाहिए, जब तक कि दोनों पक्ष सार्वजनिक मंचों के समक्ष समाधान पर मध्यस्थता का स्वेच्छा से विकल्प नहीं चुनते।

फेयर एयर इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड बनाम एन. के. मोदी (1996) 6 एस. सी. सी. 385, खंड

8 मध्यस्थता अधिनियम, 1996 पर 1986 के अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विचार किया गया था।

“16. इसलिए, यह स्पष्ट होगा कि विधायिका सहमति मध्यस्थता के अलावा एक उपाय प्रदान करने का इरादा रखती है जिसे मध्यस्थता अधिनियम के तहत लागू किया जा सकता है या जिसके तहत किसी मुकदमे में दीवानी कार्रवाई की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान। इसके द्वारा, जैसा कि देखा गया है, अधिनियम की धारा 34 एक स्वचालित अधिकार प्रदान नहीं करती है और न ही अधिनियम के तहत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा शक्ति के प्रयोग पर एक स्वचालित प्रतिबंध बनाती है। यह विवेक की बात है। इस दृष्टिकोण से विचार करते हुए, हमारा मानना है कि यद्यपि जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग न्यायिक प्राधिकरण हैं, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के उद्देश्य के लिए, अधिनियम के उद्देश्य को देखते हुए और उसकी धारा 3 के संचालन द्वारा, हमारा विचार है कि यह उचित होगा कि अधिनियम के तहत बनाए गए ये मंच पक्षों के बीच किए गए अनुबंध के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही के लिए पक्षकारों को हटाने के बजाय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मामलों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका कारण यह है कि अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बोज़िल मध्यस्थता कार्यवाही या दीवानी कार्रवाई से मुक्त करना है जब तक कि मंच अपने दम पर और किसी विशेष मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि विवादों के निर्णय के लिए उपयुक्त मंच अन्यथा वे होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

पुनः, इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न आया वह यह था कि क्या समझौते में मध्यस्थता खंड का अस्तित्व उपभोक्ता न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर देगा और क्या उपभोक्ता न्यायालय मामले को मध्यस्थता के संदर्भ के लिए भेजने के लिए बाध्य है। इस मामले में

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड बनाम एम. मधुसूदन रेड्डी और अन्य (2012) 2 एस. सी. सी. 506 और इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया:

“64. अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार, यदि उत्पादकों ने मध्यस्थता के लिए आवेदन किया था, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में मध्यस्थता खंड से उत्पन्न विवाद को एक उपयुक्त मध्यस्थ के पास भेजा जाना था और जिला उपभोक्ता मंच उनकी शिकायत पर विचार करने के हकदार नहीं थे। यह तर्क अपीलार्थी की मुख्य आपत्ति के विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है कि अपीलार्थी द्वारा बेचे गए/आपूर्ति किए गए दोषपूर्ण बीजों के उपयोग के कारण पर्याप्त नुकसान होने का दावा करने वाले किसानों और उत्पादकों के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय बीज अधिनियम की धारा 19 और/या 21 के तहत कार्रवाई करने के लिए संबंधित बीज निरीक्षकों के साथ शिकायत करना था।

65. इस मुद्दे पर विचार की शुरुआत इस अवलोकन के साथ की जानी चाहिए कि एक किसान/उत्पादक की शिकायत, जिसने अपीलार्थी या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा बेचे गए/आपूर्ति किए गए दोषपूर्ण बीजों के उपयोग के कारण फसल के नुकसान या विफलता के कारण वित्तीय रूप से लाभ उठाया है, बीज के विक्रेता/आपूर्तिकर्ता पर मुकदमा चलाकर दूर नहीं किया जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति दोषी पाया जाता है और कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो भी पीड़ित किसान/उत्पादक को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए, बीजों के विक्रेता/आपूर्तिकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित बीज निरीक्षक के पास शिकायत दर्ज करने के लिए एक पीड़ित किसान/उत्पादक के लिए उपलब्ध तथाकथित उपाय को भ्रामक नहीं माना जा सकता है और उसे एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राहत से वंचित नहीं किया जा सकता है।

66. एक उत्पादक के लिए मध्यस्थता का उपाय ही एकमात्र उपाय नहीं है। बल्कि, यह एक वैकल्पिक उपचार है। वह या तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किसी मध्यस्थ से संपर्क कर सकता है या शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि उत्पादक मध्यस्थता के उपाय का विकल्प चुनता है, तो यह कहना संभव हो सकता है कि वह बाद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है। हालाँकि, यदि वह सक्षम उपभोक्ता मंच के समक्ष पहली बार में शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुनता है, तो उसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 का आह्वान करके राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 3 की सरल भाषा यह स्पष्ट करती है कि उस अधिनियम में उपलब्ध उपाय उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त है और उनका अपमान नहीं है।”

बाद में, इस अदालत के समक्ष इसी तरह के एक मामले में [रोज़डेल डेवलपर्स]

प्राइवेट लिमिटेड बनाम अघोर भट्टाचार्य और अन्य **(2018) 11 एससीसी 337]**,

मध्यस्थता के लिए बिल्डर की याचिका को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए "तुच्छ मुकदमेबाजी" के रूप में बहुत हद तक खारिज कर दिया गया था।

10. अपीलार्थियों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया एक अन्य प्रश्न यह है कि चूंकि यह बिल्डर है जिसने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए धारा 11 के तहत एक आवेदन के माध्यम से "अदालत" का दरवाजा खटखटाया था, समझौते के संदर्भ में, उपभोक्ता को उपभोक्ता मंच के समक्ष उपचार की मांग करने के बजाय, सभी निष्पक्षता में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, जैसा कि पक्षों के बीच (उनके समझौते में) सहमति हुई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

हालाँकि, सवाल चुनाव या पसंद का है, न कि किस पक्ष ने पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विवाद की प्रकृति होगी, जो इसके निवारण के लिए मंच का निर्धारण करेगी। कानून उपभोक्ता को यह विकल्प देता है कि वह या तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपचार का लाभ उठा सके, न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज करा सके या मध्यस्थता के लिए जा सके। यह विकल्प बिल्डर के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वे 2019 के अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' नहीं हैं। यह यहाँ प्रत्यर्थी श्रीमती हैं। बी. उदयश्री जिन्हें निजी मंच यानी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने या उपभोक्ता मंच, जो एक सार्वजनिक मंच है, के समक्ष शिकायत करने के बीच "विकल्प" चुनना होता है। उसने बाद वाले के पास जाने का फैसला किया है। बिल्डर के धारा 11 के आवेदन पर तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष उनका जवाब मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए उनका प्रस्तुतिकरण नहीं है। अपने उत्तर में, वह जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष एक उपभोक्ता के रूप में अपने द्वारा की गई शिकायत के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित करती है, जो एक 'न्यायिक प्राधिकरण' है और इसलिए मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 8 लागू होगी, न कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत आवेदन।

अब केवल इसलिए कि बिल्डर ने पहले न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था (मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत) स्वयं उपभोक्ता न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को नहीं हटाएगा। न्यायालय की अधिकारिता सबसे पहले सबसे तेजी से तय होने वाले मामले से निर्धारित नहीं होती है, बल्कि विवाद की प्रकृति, मामले में सार्वजनिक नीति, विधायिका की इच्छा, विभिन्न कारकों के बीच उपभोक्ता के चुनाव या पसंद से निर्धारित होती है।

11. कोई भी संदेह जो अब तक उपभोक्ता मंचों के समक्ष अपने उपचार का पीछा करने वाले उपभोक्ता के लिए 'मध्यस्थता' के लिए जाने के खिलाफ मौजूद हो सकता है, हालाँकि एक मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष होने के नाते, अब एम्मार III (ऊपर) में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शांत हो गया है। यह निर्णय इस कारण से महत्वपूर्ण नहीं है कि इसने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 11 में उप-धारा 6 ए और धारा 8 में उप-धारा 1 को शामिल करने के आलोक में पूरे मुद्दे की नए सिरे से जांच की है।

इस मामले की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि क्रम में होनी चाहिए क्योंकि इस न्यायालय ने वर्तमान विवाद का निर्धारण करते समय उपरोक्त निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया है। हमें यहां राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन. सी. डी. आर. सी.) की एक बड़ी पीठ के दिनांकित विस्तृत आदेश का भी उल्लेख करना चाहिए।

13.07.2017 आफताब सिंह बनाम एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड और ए. एन. आर., 2017 एस. सी. सी.

ऑनलाइन एन. सी. डी. आर. सी. **1614** ("एम्मार I") जिसने एम्मार III (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि निर्धारित की थी।

2016 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 8 और 11 में एक संशोधन शामिल किया गया था। यह संशोधन 2016 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा डब्ल्यू. ई. एफ. 23.10.2015 में शामिल किया गया था। ये इस प्रकार हैं:

पूर्व-संशोधन	संशोधन के बाद
धारा 8: 8. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां एक मध्यस्थता समझौता होता है। — (1) एक न्यायिक प्राधिकरण, जिसके समक्ष एक ऐसे मामले में कार्रवाई की जाती है जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, यदि कोई पक्ष विवाद के सार पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करते समय बाद में लागू नहीं होता है, तो पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मूल मध्यस्थता समझौते या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रतियों के साथ न हो।	धारा 8: 8. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां एक मध्यस्थता समझौता होता है। — (1) एक न्यायिक प्राधिकरण, जिसके समक्ष किसी ऐसे मामले में कार्रवाई की जाती है जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, यदि मध्यस्थता समझौते का कोई पक्षकार या उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला कोई व्यक्ति, विवाद के सार पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करने की तारीख के बाद लागू नहीं होता है, तो, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए तब तक संदर्भित करता है जब तक कि वह यह नहीं मानता है कि प्रथम दृष्टया कोई वैध

	मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है। (2) उप- धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मूल मध्यस्थता समझौते या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रतियों के साथ न हो। बशर्ते कि जहां मूल मध्यस्थता समझौता या उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि उप-धारा (1) के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के लिए आवेदन करने वाले पक्ष के पास उपलब्ध नहीं है और
--	---

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

(3)	उक्त समझौते या प्रमाणित संशोधित प्रति को उस समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा रखा जाता है, फिर, इस प्रकार आवेदन करने वाला पक्ष मध्यस्थता समझौते की एक प्रति और एक याचिका के साथ ऐसा
-------------	--

	आवेदन करेगा जिसमें अदालत से अनुरोध किया जाएगा कि वह दूसरे पक्ष से मूल मध्यस्थता समझौते या उसकी विधिवत प्रमाणित संशोधित प्रति को उस अदालत के समक्ष पेश करने के लिए कहे। (3)
धारा 11: मध्यस्थों की नियुक्ति। — (1) (2) (3) (4) यदि उप-धारा (3) में नियुक्ति प्रक्रिया लागू होती है और- (क)। (ख) दोनों नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं, नियुक्ति, एक पक्ष के अनुरोध पर, मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा की जाएगी। (5) एकल मध्यस्थ के साथ मध्यस्थता में, उप-धारा (2) में	धारा 11: मध्यस्थों की नियुक्ति। — (1) (2) (3) (4) यदि उप-धारा (3) में नियुक्ति प्रक्रिया लागू होती है और- (क). (ख) दो नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तो नियुक्ति किसी पक्ष के अनुरोध पर, उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी; (5) उप-धारा (2)

निर्दिष्ट किसी समझौते में विफल होना, यदि पक्षकार मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं।	में निर्दिष्ट किसी समझौते में विफल रहने पर, एकल मध्यस्थ के साथ मध्यस्थता में, यदि पक्षकार मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं।
--	---

275

एसएमटी। एम. हेमलाथा देवी और ओआरएस बनामबी. उदयश्री [सुधांशु धूलिया, जे.] 276

एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से इस तरह से सहमत होने का अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिन बाद, किसी पक्ष के अनुरोध पर, मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा नियुक्ति की जाएगी। (6) जहां, पार्टियों द्वारा सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत, -(ए). (बी)। (ग) एक व्यक्ति, एक संस्था सहित, उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपे गए	एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से इस तरह से सहमत होने का अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिन बाद, किसी पक्ष के अनुरोध पर, सर्वोच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा नियुक्ति की जाएगी। (6) जहां पक्षकारों द्वारा सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत-(क). (ख). (ग) कोई व्यक्ति,
--	---

किसी भी कार्य को करने में विफल रहता है, एक पक्ष मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति या संस्थान से आवश्यक उपाय करने का अनुरोध कर सकता है, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया पर समझौता नियुक्ति को सुरक्षित करने के लिए अन्य साधन प्रदान नहीं करता है।

जिसमें कोई संस्था भी शामिल है, उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपे गए किसी कार्य को करने में विफल रहता है, कोई पक्षकार उच्चतम न्यायालय या, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्थान से आवश्यक उपाय करने का अनुरोध कर सकता है, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया पर समझौता नियुक्ति प्राप्त करने के लिए अन्य साधन प्रदान नहीं करता है
(6 क)
उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय, उप-धारा (4) या उप-धारा

	(5) या उप-धारा (6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, परीक्षा को स्वीकार करेगा।
--	---

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
[2023] 13 एस सी आर।

	(6(ख)) उच्चतम न्यायालय या, यथास्थिति, उच्च न्यायालय द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या संस्था के पदनाम को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक शक्ति के प्रत्यायोजन के रूप में नहीं माना जाएगा।
--	---

अब संशोधन के बाद, धारा 8 की नई निगमित उप-धारा (1) में ये शब्द हैं "सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए तब तक संदर्भित करें जब तक कि यह विश्वास न हो कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है।" जब शिकायतों का नेतृत्व उपभोक्ता मंच के समक्ष किया जाता था, तो ऐसे मामलों को एन. सी. डी. आर. सी. की तीन सदस्यीय बड़ी पीठ को भेजा जाता था। संदर्भित प्रश्न यह था कि क्या न्यायिक प्राधिकरण यानी उपभोक्ता मंच के पास कोई विकल्प (संशोधन के बाद) था, लेकिन जब धारा 8 के तहत एक आवेदन उसके सामने रखा जाता है तो विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाता है। एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा एक सुविचारित आदेश में दिया गया उत्तर यह मानता है कि उपभोक्ता मंच के समक्ष विवाद की मध्यस्थता पर कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसलिए उपभोक्ता न्यायालय मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

एन. सी. डी. आर. सी. दिनांक 2 के इस निर्णय को बिल्डर द्वारा इस अदालत के समक्ष अपनी वैधानिक अपील में चुनौती दी गई थी, जिसे एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम एन. सी. डी. आर. सी. में दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से संक्षेप में खारिज कर दिया गया था।

आफताब सिंह, **2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 2378 ("एम्मार II")**।

इसके बाद इस न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की गई जिसमें दिनांकित **13.02.2018** आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी। इसलिए इस अदालत द्वारा **2016** के संशोधन के आलोक में मामले पर पुनर्विचार किया गया था और सवाल यह था कि क्या संशोधन अब इस अदालत के पहले के दृष्टिकोण के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। इस न्यायालय ने पक्षों को व्यापक सुनवाई देने के बाद अपने पहले के विचारों को दोहराते हुए कहा कि अधिनियम में संशोधन से पहले की गई कानूनी स्थिति में कोई अंतर नहीं आएगा।

12. अपीलार्थियों का मुख्य तर्क यह था कि वर्ष **2016** (2016 का अधिनियम संख्या 3) में संशोधन के बाद, जिसके द्वारा संसद ने "किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद" शब्द जोड़ा था, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए तब तक संदर्भित करता है जब तक कि यह विश्वास न हो कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है, विधायी इरादा स्पष्ट था कि इसके बाद न्यायिक **277**

एसएमटी। एम. हेमलाथा देवी और ओआरएस बनाम बी. उदयश्री [सुधांशु धूलिया, जे.] **278**

प्राधिकरण को एक बार वैध मध्यस्थता समझौता होने के बाद मध्यस्थता के लिए एक विवाद को संदर्भित करने के लिए अनिवार्य किया जाता है, और धारा 8 के तहत एक आवेदन विधिवत प्रस्तुत किया जाता है। तर्क यह था कि यद्यपि संशोधन से पहले, और राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपचार का लाभ उठाने का विकल्प उपलब्ध था, लेकिन संशोधन के बाद और धारा 8 की स्पष्ट भाषा के संदर्भ में, न्यायिक प्राधिकरण के पास

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत न्यायिक अधिकारियों के समक्ष आवेदन किए जाने पर विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अपीलार्थियों द्वारा हमारे समक्ष भी यही तर्क दिया गया है, हालांकि उच्च न्यायालय के समक्ष उनके धारा 11 के आवेदन के संदर्भ में, वे तर्क देंगे कि धारा 11 की उप-धारा 6 ए में अब दिए गए समान जनादेश को देखते हुए, उच्च न्यायालय के पास मध्यस्थ नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।¹³ इस न्यायालय के समक्ष उपभोक्ता की ओर से (एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड मामले में) यह प्रतिवाद किया गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के लिए एक लाभकारी कानून है, जो उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए एक त्वरित और त्वरित उपाय प्रदान करता है। यदि पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार किया जाता है तो यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जैसे लाभकारी विधान को शून्य करने के बराबर होगा। न्यासों, किरायेदारी विवादों, औद्योगिक विवादों, आईपीआर और अन्य गैर-मध्यस्थता विवादों से संबंधित मामलों में भी इसका समान प्रभाव होगा। यही कारण था कि एम्मार I (ऊपर) में एन. सी. डी. आर. सी. की तीन सदस्यीय पीठ ने

उन्होंने कहा, "धारा 8 (1) में संशोधन की लहर इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि अन्य विधानों और न्यायशास्त्र के क्षेत्रों को, विशेष रूप से इन संबंधित कानूनों की नींव के साथ किसी भी जुड़ाव, बहस और आलोचना के बिना, विधायिकाओं और न्यायालयों द्वारा बड़ी मेहनत से बनाया गया है।"

14. इस न्यायालय ने तब कानूनी स्थिति की जांच की क्योंकि यह संशोधनों और कानूनी स्थिति पर संशोधन के प्रभाव से पहले मौजूद थी। 1986 के अधिनियम की प्रस्तावना की जांच की गई थी।³ 1986 का अधिनियम उपभोक्ता हित की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और इसके स्तर को बढ़ाने के लिए बनाया गया था।

3 हालांकि 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अब निरस्त कर दिया गया है और 2019 का नया अधिनियम यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू हो गया है, फिर भी हमारे उद्देश्य के लिए वर्तमान निर्णय में विभिन्न स्थानों पर 1986 के अधिनियम के संदर्भ से कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि 1986 के अधिनियम और 2019 अधिनियम का मूल उद्देश्य मुख्य रूप से उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उन्हें उनकी शिकायतों का एक आसान, सस्ता निवारण तंत्र प्रदान करना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

बाजार संचालित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के लिए अच्छा खेल खेलना। 1986 के अधिनियम को लखनऊ विकास में एक लाभकारी कानून के रूप में माना गया था।

प्राधिकरण बनाम एम. के. गुप्ता (1994) 1 एस. सी. सी. 243। यह इस प्रकार माना गया था:

".....अधिनियम की प्रस्तावना के साथ शुरू करने के लिए, जो विधायी इरादे का पता लगाने के लिए उपयोगी सहायता प्रदान कर सकता है, इसे 'उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा

प्रदान करने के लिए' अधिनियमित किया गया था। 'संरक्षण' शब्द का उपयोग अधिनियम के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी प्रदान करता है। विभिन्न अवज्ञाएं और प्रावधान जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने का विस्तृत रूप से प्रयास करते हैं, उन्हें इस दृष्टिकोण से अलग किए बिना इस प्रकाश में समझा जाना चाहिए कि एक प्रस्तावना किसी प्रावधान के अन्यथा स्पष्ट अर्थ को नियंत्रित नहीं कर सकती है। वास्तव में कानून आम आदमी को ऐसी गलतियों से बचाने की लंबे समय से महसूस की गई आवश्यकता को पूरा करता है, जिसके लिए विभिन्न कारणों से सामान्य कानून के तहत उपाय भ्रामक हो गया है। राज्य को हस्तक्षेप करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की अनुमति देने वाले विभिन्न कानून और विनियम बेईमान लोगों के लिए एक पनाहगाह बन गए हैं क्योंकि प्रवर्तन तंत्र या तो नहीं चलता है या यह सक्रिय रूप से, निष्क्रिय रूप से और उन कारणों से चलता है जो बताए जाने की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम का महत्व उपभोक्ता को बाजार अर्थव्यवस्था में सीधे भाग लेने में सक्षम बनाकर समाज के कल्याण को बढ़ावा देने में निहित है। यह एक उपभोक्ता की असहायता को दूर करने का प्रयास करता है जिसका सामना वह शक्तिशाली व्यवसाय के खिलाफ करता है, जिसे 'रैकेटों का एक नेटवर्क' या एक ऐसे समाज के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें 'उत्पादकों ने' बाकी को लूटने 'के लिए शक्ति प्राप्त की है और सार्वजनिक निकायों की शक्ति जो निष्क्रियता के भंडार में पतित हो रहे हैं, जहां कागजात कर्तव्य और जिम्मेदारी के रूप में एक मेज से दूसरी मेज पर नहीं जाते हैं, बल्कि आम आदमी को असहाय, भ्रमित और हैरान करने वाले बाहरी विचार के लिए जाते हैं। यह बीमारी इतनी व्यापक, व्यापक और गहरी होती जा रही है कि समाज इसे परेशान करने, शिकायत करने और इसके खिलाफ बोलने के बजाय इसे जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार कर रहा है। इन अविश्वसनीय लेकिन कठोर वास्तविकताओं में अधिनियमन एक चांदी की परत प्रतीत होता है, जो समय के साथ सड़ांध को रोकने में सफल हो सकता है।”

सचिव, थिरुमुरुगन सहकारी कृषि ऋण समिति

वी.एम. ललिता, **(2004) 1 एस. सी. सी. 305**, पैरा **11** और **12** में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

“**11.** उद्देश्यों और कारणों के विवरण और **1986** के अधिनियम की योजना से यह स्पष्ट है कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के हितों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है और **279**

एसएमटी। एम. हेमलाथा देवी और ओआरएस बनाम बी. उदयश्री [सुधांशु धूलिया, जे.] **280**

इसका उद्देश्य बेहतर निवारण तंत्र प्रदान करना है, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ता, आसान, त्वरित और प्रभावी निवारण उपलब्ध कराया जाता है। अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अर्ध-न्यायिक मंचों की स्थापना की जाती है, जिनमें व्यापक शक्तियां निहित होती हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए इन अर्ध-न्यायिक मंचों को एक विशिष्ट प्रकृति की राहत देने और जहां भी उचित हो,

उपभोक्ताओं को मुआवजा देने और उनके आदेशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार है।

12. अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे। अधिनियम की योजना और उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर तरीके से रक्षा करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त/विस्तारित अधिकार क्षेत्र को अर्थ देने के लिए वर्तमान मामले के संदर्भ में प्रावधानों की व्यापक, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण रूप से व्याख्या की जानी चाहिए, विशेष रूप से जब धारा 3 अन्य अधिनियमों के तहत प्रदान किए गए अन्य उपायों के अलावा अधिनियम के तहत उपचार प्रदान करने का प्रयास करती है, जब तक कि कोई स्पष्ट प्रतिबंध न हो।”

यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1986 का अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और एक निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो सस्ता, आसान, त्वरित और प्रभावी है। इस उद्देश्य के लिए, इन न्यायिक प्राधिकरणों में निहित व्यापक शक्तियों के साथ जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अर्ध-न्यायिक मंचों की स्थापना की गई थी। इन न्यायिक प्राधिकरणों को एक विशिष्ट प्रकृति की राहत देने और जहां भी उनके आदेशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाने की आवश्यकता महसूस की गई, वहां उपभोक्ता को मुआवजा देने की शक्तियां निहित थीं और न्यायिक प्राधिकरणों को ऐसी शक्तियां निहित थीं। अब इसकी तुलना मध्यस्थ की शक्ति से करें। मध्यस्थ के पास जुर्माना लगाने की शक्ति नहीं होती है। यह दोनों मंचों के बीच आवश्यक अंतरों में से एक है। यह निश्चित रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि 1986 के अधिनियम के तहत दिए गए प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य प्रावधान या किसी अन्य कानून के अतिरिक्त थे, और उनके अपमान में नहीं थे।

15. फेयर एयर इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड (ऊपर) और स्काईपैक कोरियर्स लिमिटेड में।

बनाम टाटा केमिकल्स लिमिटेड, **(2000) 5 एस. सी. सी. 294** इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति को दोहराया गया था। राष्ट्रीय बीज निगम में इस न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

इस निर्णय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में सीमित (उपर्युक्त) का भी उल्लेख किया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उपभोक्ता के लिए मध्यस्थता ही एकमात्र उपाय नहीं है और वे या तो मध्यस्थता का संदर्भ ले सकते हैं या 1986 के अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन अनुबंध में मध्यस्थता समझौते के बावजूद केवल मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत उपचार लेने के लिए कभी भी मजबूर नहीं किया जा सकता है।

इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा रोज़डेल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में दोहराया गया था, जिसमें पैरा **4,6** और **7** में निम्नानुसार कहा गया है:

“4. हमारी राय में, विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं है। यह प्रश्न कि क्या मध्यस्थता खंड का अस्तित्व है

पक्षों के बीच निष्पादित समझौते में निहित उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है और किसी भी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर, उपभोक्ता मंच मध्यस्थ का संदर्भ देने के लिए कर्तव्यबद्ध है, जिस पर राष्ट्रीय बीज निगम में व्यापक रूप से विचार किया गया था। लिमिटेड वी.एम. मधुसूदन रेड्डी [राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड वी.एम. मधुसूदन रेड्डी, (2012) 2 एससीसी 506:(2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 908] और यह देखा गया।

5.....

6. श्री घोष द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उनका इस अपील में उठाए गए मुद्दे पर कोई असर नहीं है। इनमें से किसी भी मामले में, इस न्यायालय ने 1986 के अधिनियम में निहित प्रावधानों के आलोक में 1996 के अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या नहीं की है। इसलिए, उन निर्णयों में दिए गए प्रस्तावों कि 1996 के अधिनियम की धारा 8 अनिवार्य है, से यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि उपभोक्ता मंच मध्यस्थ न्यायाधिकरण को निर्देश देने के लिए बाध्य है।

7. निरस्त कानूनी स्थिति को देखते हुए, राष्ट्रीय आयोग

यह अभिनिर्धारित करके कोई त्रुटि नहीं की कि शिकायतकर्ता के लिए उपलब्ध मध्यस्थता का उपाय उपभोक्ता मंचों के अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं करता है और उपभोक्ता मंच मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजने के लिए बाध्य नहीं हैं। उपरोक्त अवलोकन के साथ, अपील खारिज कर दी जाती है।”

16. इस न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के दोनों प्रावधानों पर विचार करते हुए निर्णयों की एक श्रृंखला में कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक विशेष और लाभकारी विधान होने के कारण इसमें प्रदान किए गए उपाय विशेष उपाय हैं।

एसएमटी। एम. हेमलाथा देवी और ओआरएस बनाम बी. उदयश्री [सुधांशु धूलिया, जे.] 282

और एक उपभोक्ता को उनसे वंचित नहीं किया जा सकता है यदि वह पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौते के बावजूद इस तरह के उपाय का लाभ उठाने का विकल्प चुनता है। यह उपभोक्ता को प्रदान किया जाने वाला एक उपाय है जहां उपभोक्ता उसे प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं में से किसी एक में दोष का सामना करता है और इसलिए वह विधायिका द्वारा उसे प्रदान किए गए उपभोक्ता मंच के समक्ष अपनी शिकायतों का निवारण चाहता है। इस मामले में कई

उदाहरणों का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने एम्मार III (ऊपर) में कहा था कि न केवल 1986 के अधिनियम के तहत कार्यवाही विशेष कार्यवाही है जो मध्यस्थता समझौते के बावजूद अधिनियम के तहत जारी रहेगी, बल्कि बड़ी संख्या में अन्य कार्यवाही भी होगी जो मध्यस्थता समझौते के बावजूद जारी रहना चाहिए जैसे कि आपराधिक न्यायालय में कार्यवाही, एक विशेष प्रकृति का वाणिज्यिक विवाद या कोई अन्य गैर-मध्यस्थता विवाद। एम्मार III (ऊपर) के पैरा 30 में, यह निम्नानुसार कहा गया था:

“30. न केवल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की कार्यवाहियां विशेष कार्यवाहियां हैं जिन्हें मध्यस्थता समझौते के बावजूद अधिनियम के तहत जारी रखने की आवश्यकता थी, बल्कि बड़ी संख्या में अन्य ऐसे मामले भी हैं जहां मध्यस्थता समझौता न तो कार्यवाही को रोक सकता है और न ही बाधित कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी पक्ष की किसी भी कार्रवाई, किसी व्यक्ति की चूक या कमीशन की, जो एक अपराध के बराबर है, आपराधिक अदालत द्वारा जांच की जानी चाहिए और पक्षकारों के बीच समझौते की कोई राशि उक्त मामले के लिए प्रासंगिक नहीं होगी। उदाहरण के लिए, दो पक्षों के बीच एक वाणिज्यिक समझौता हो सकता है कि लेनदेन से संबंधित सभी मुद्दों को समझौते में मध्यस्थता खंड के अनुसार मध्यस्थता द्वारा तय किया जाना है। ऐसे मामले में जहां लेनदेन में एक पक्ष द्वारा चेक का अनादर किया जाता है, मध्यस्थता समझौते के बावजूद पीड़ित पक्ष को आपराधिक अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इसी तरह, कई ऐसे मुद्दे हैं जो गैर-मध्यस्थ हैं। मध्यस्थता समझौते के आधार पर किसी विवाद का निर्णय नहीं लेने के लिए स्पष्ट या निहित दोनों तरह का प्रतिबंध हो सकता है।”

17. बूज एलन और हैमिल्टन इंक. (ऊपर) में, गैर-क्या होगा?

इस न्यायालय द्वारा मध्यस्थता विवाद को विस्तार से बताया गया था। एम्मार III (ऊपर) ने तब विश्लेषण किया कि क्या मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में 2016 के संशोधन के बाद यह स्थिति बदल गई है। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में जिन प्रावधानों में संशोधन किया गया है, विशेष रूप से जिनके बारे में हम यहां चिंतित हैं, यानी धारा 8 और 11 का उल्लेख पहले ही पिछले पैराग्राफ में किया जा चुका है। एम्मार III (ऊपर) में इस न्यायालय ने, संशोधन के बाद प्रावधानों में बदलाव के बाद, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (3) को संदर्भित किया, जो निम्नानुसार है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

“2. (3) यह भाग उस समय लागू किसी अन्य कानून को लागू नहीं करेगा जिसके आधार पर कुछ विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।”

इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 (अर्थात्, भाग 1) का यह भाग उस समय लागू किसी अन्य कानून को लागू नहीं करेगा जिसके आधार पर कुछ विवादों को

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जिन विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उन्हें पहले ही ऊपर संदर्भित किया जा चुका है और बूज एलन और हैमिल्टन इंक. (ऊपर) में विस्तार से चर्चा की गई है। पुनरावृत्ति के लिए और केवल एक उदाहरण बनाने के लिए, ये विवाद होंगे:

- (i) पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट; (ii) एंटी-ट्रस्ट/प्रतिस्पर्धा कानून;
- ((iii) दिवाला/परिसमापन; (iv) रिश्त/भ्रष्टाचार; (v) धोखाधड़ी;
- ((vi) आपराधिक मामला।

ए. अय्यासामी बनाम ए. परमशिवम और अन्य **(2016) 10 एससीसी 386** में,

इस न्यायालय ने पैरा 35 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

“35. आम तौर पर प्रत्येक दीवानी या वाणिज्यिक विवाद, चाहे वह अनुबंध पर आधारित हो या अन्यथा, जो एक दीवानी अदालत द्वारा तय किया जा सकता है, सिद्धांत रूप में मध्यस्थता समझौते द्वारा शासित होने वाले विवाद के अधीन मध्यस्थता द्वारा निर्णय लेने और हल करने में सक्षम है, जब तक कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता को या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा बाहर नहीं किया जाता है। बूज एलन और हैमिल्टन इंक. बनाम एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड. [बूज एलन एंड हैमिल्टन इंक. बनाम एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड, (2011) 5 एस. सी. सी. 532: (2011) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 781], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि (एस. सी. सी. पृष्ठ 546, पैरा 35 में) कार्यवाही की कुछ श्रेणियों का निर्णय विधायिका द्वारा सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में विशेष रूप से सार्वजनिक मंचों के लिए आरक्षित है। कुछ अन्य श्रेणियों के मामले, हालांकि विशेष रूप से न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय के लिए आरक्षित नहीं हैं, आवश्यक निहितार्थ से निजी मंचों के दायरे से बाहर हो सकते हैं। इस न्यायालय ने गैर-मध्यस्थता विवादों के कुछ उदाहरण दिए जैसे कि: (एस. सी. सी. पीपी. 546-47, पैरा 36)

283

एसएमटी। एम. हेमलाथा देवी और ओआरएस बनाम बी. उदयश्री [सुधांशु धूलिया, जे.] 284

(i) अधिकारों और देनदारियों से संबंधित विवाद जो आपराधिक अपराधों को जन्म देते हैं या उत्पन्न होते हैं;

((ii) तलाक, न्यायिक अलगाव, वैवाहिक अधिकारों की बहाली और बाल अभिरक्षा से संबंधित वैवाहिक विवाद;

((iii) संरक्षकता के मामले; (iv) दिवाला और परिसमापन;

(v) वसीयती मामले, जैसे प्रोबेट का अनुदान, प्रशासन के पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र; और

(vi) बेदखली या किरायेदारी के मामले विशेष कानूनों द्वारा शासित होते हैं जहां एक किरायेदार को बेदखली के खिलाफ विशेष सुरक्षा प्राप्त होती है और विशिष्ट अदालतों को विवाद से निपटने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कार्यों का यह वर्ग आर. ई. एम. में काम करता है, जो व्यक्तिगत रूप से अधिकार के विपरीत बड़े पैमाने पर दुनिया के खिलाफ प्रयोग करने योग्य अधिकार है जो विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ संरक्षित हित है। व्यक्तिगत रूप से अधिकारों से संबंधित सभी विवादों को मध्यस्थता के लिए उत्तरदायी माना जाता है, जबकि संबंधित अधिकारों पर अदालतों और सार्वजनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। बंधक के प्रवर्तन को आर. ई. एम. में एक अधिकार माना गया है जिसके लिए मध्यस्थता में कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं होगी। विमल किशोर शाह बनाम जायेश दिनेश शाह [विमल किशोर शाह बनाम जायेश दिनेश शाह, (2016) 8 एस. सी. सी. 788:(2016) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 303], इस न्यायालय ने बूज एलन [बूज एलन एंड हैमिल्टन इंक. बनाम. में निर्धारित छह गैर-मध्यस्थता श्रेणियों में मामलों की सातवीं श्रेणी को जोड़ा। एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड, (2011) 5 एस. सी. सी. 532:(2011) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 781], अर्थात् न्यास विलेख और न्यास अधिनियम से उत्पन्न न्यासों, न्यासियों और लाभार्थी निकायों से संबंधित विवाद।

18. इस न्यायालय ने एम्मार III (ऊपर) में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 5 के दायरे और प्रभाव पर विचार किया जो निम्नानुसार है:

“5. न्यायिक हस्तक्षेप का विस्तार।- तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस भाग द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायिक प्राधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय इसके कि इस भाग में ऐसा उपबंध किया गया हो।”

19. फिर वे कौन से कारक थे जिनके कारण मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 8 और 11 में संशोधन की आवश्यकता पड़ी और इन संशोधनों के पीछे क्या उद्देश्य था? इस पहलू की फिर से जांच की गई है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

एम्मार III (ऊपर) में विवरण। विधि आयोग ने अपनी 246 वीं रिपोर्ट में इस तरह के संशोधनों की सिफारिश की थी, विधि आयोग की 246 वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 33 में कहा गया था:

“33. इस संदर्भ में आयोग ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 और 11 में संशोधन की सिफारिश की है। न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा केवल उन स्थितियों तक सीमित है जहां न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण यह मानता है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या अमान्य है। जहाँ तक हस्तक्षेप की प्रकृति का संबंध है, यह अनुशंसा की जाती है कि यदि

न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण मध्यस्थता समझौते को चुनौती देने वाले तर्क के खिलाफ प्रथम दृष्टया संतुष्ट होता है, तो वह मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और/या पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजेगा, जैसा भी मामला हो। संशोधन में परिकल्पना की गई है कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षकारों को केवल तभी मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं करेगा जब वह यह मानता है कि कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या यह अमान्य है। यदि न्यायिक प्राधिकरण की राय है कि प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौता मौजूद है, तो वह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा, और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ देगा। हालाँकि, यदि न्यायिक प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि समझौता मौजूद नहीं है, तो निष्कर्ष शून्य होगा और प्रथम दृष्टया नहीं।”

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

“2. इस अधिनियम को कम से कम अदालत के हस्तक्षेप के साथ मध्यस्थता से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। समय बीतने के साथ, अधिनियम की प्रयोज्यता में कुछ भिन्नताएं देखी गई हैं। कुछ मामलों में अदालतों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या के परिणामस्वरूप मध्यस्थता कार्यवाही के निपटारे में देरी हुई है और मध्यस्थता मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप बढ़ा है, जो अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देता है।

*

*

*

6. ((iv) यह प्रावधान करना कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करेगा न कि अन्य मुद्दों की; धारा 8 में संशोधन पर खंडों पर टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं: “विधेयक के खंड 4 में मूल अधिनियम की धारा 8 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है ताकि यह निर्दिष्ट किया जा सके कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षों को मध्यस्थता 285 के लिए भेजेगा।

एसएमटी। एम. हेमलाथा देवी और ओआरएस बनामबी. उदयश्री [सुधांशु धूलिया, जे.] 286

जब तक यह नहीं माना जाता है कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है। उप-धारा (2) के नीचे एक परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया गया है कि जहां मूल मध्यस्थता समझौता या उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उस पक्ष के पास उपलब्ध नहीं है जो उप-धारा (1) के तहत आवेदन करता है, और दूसरे पक्ष द्वारा रखी जाती है, तो ऐसा पक्ष मध्यस्थता समझौते की एक प्रति उप-धारा (1) के तहत आवेदन के साथ न्यायालय से अनुरोध

करेगा कि वह दूसरे पक्ष से मूल मध्यस्थता समझौते या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रतियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए कहे।

उप-धारा (6-ए) अंतःस्थापित करके धारा 11 में संशोधन पर निम्नलिखित कहा गया था:

“विधेयक का खंड 6 मूल अधिनियम की धारा 11 में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि मध्यस्थ की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बजाय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। उप-धारा (6-ए) को यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उप-धारा (4) से (6) के तहत आवेदन पर विचार करते समय मध्यस्थता समझौते की जांच करने के लिए आश्वस्त नहीं होगा।”

20. मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 8 में किया गया संशोधन इस न्यायालय के समक्ष अमित लालचंद मामले में विचार के लिए आया।

शाह बनाम ऋषभ एंटरप्राइजेज, **(2018) 15 एस. सी. सी. 678**, जहां पैरा **28** और **30**, यह निम्नानुसार कहा गया था:

“28. ‘2015 के संशोधनों द्वारा धारा 8 (1) में मुख्य रूप से चार संशोधन पेश किए गए हैं- (i) प्रासंगिक “पक्ष” जो मध्यस्थता के लिए संदर्भ की मांग करने के लिए आवेदन करने का हकदार है, उसे मध्यस्थता समझौते में ऐसे पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों को शामिल करने के लिए स्पष्ट किया गया है; (ii) न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जांच का दायरा इस बात तक सीमित है कि क्या “कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है” और न्यायिक प्राधिकरण द्वारा परीक्षा की प्रकृति को “प्रथम दृष्टया” आधार पर स्पष्ट किया गया है; (iii) कट-ऑफ तिथि जिसके द्वारा धारा 8 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया जाना है, जिसका अर्थ “एफ. आई. आर. जमा करने की तारीख” है। धारा 8 (2) के प्रावधान को एक ऐसे पक्ष को अनुमति देने के लिए जोड़ा गया है जिसके पास मध्यस्थता समझौते की मूल या प्रमाणित प्रतियां नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

दूसरे पक्ष द्वारा बनाए रखा जा रहा है, फिर भी संदर्भ मांगने के लिए धारा 8 के तहत आवेदन करने के लिए, और दूसरे पक्ष को उसी को पेश करने के लिए बुलाने के लिए।’ (संदर्भ: न्यायमूर्ति आर. एस. बचावत का मध्यस्थता और सुलह का कानून, छठा संस्करण, खंड। पी पर। (धारा 1 से 34)। 695 लेक्सिस नेक्सिस द्वारा प्रकाशित)। * * *

30. अधिनियम की धारा 8 में संशोधन की भाषा स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 8 (1) में संशोधन सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के किसी भी अनुरोध, निर्णय, डिक्री या

आदेश के बावजूद लागू होगा। उच्च न्यायालय ने [अमित लालचंद शाह बनाम ऋषभ एंटरप्राइजेज, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 7865] शब्द पर जोर दिया '। जब तक कि यह नहीं मानता है कि प्रथम दृष्टया कोई वैध समझौता मौजूद नहीं है'। उच्च न्यायालय ने कहा कि एस्टनफी एल्ड और ऋषभ के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं है। सुकन्या होल्डिंग्स [सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम. जायेश एच. पांड्या, (2003) 5 एस. सी. सी. 531] और अधिनियम की संशोधित धारा 8 और धारा 45, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 8 और धारा 45 की भाषा में अंतर की ओर इशारा किया। उच्च न्यायालय ने सुकन्या होल्डिंग्स [सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम. जायेश एच. पांड्या, (2003) 5 एस. सी. सी. 531] और क्लोरो कंट्रोल्ल्स [क्लोरो कंट्रोल्ल्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम. सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफ़ी कैशन इंक., (2013) 1 एससीसी 641:(2013) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 689] और कहा कि सुकन्या होल्डिंग्स [सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम. जायेश एच. पांड्या, (2003) 5 एस. सी. सी. 531] को क्लोरो कंट्रोल्ल्स [क्लोरो कंट्रोल्ल्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम क्लोरो कंट्रोल्ल्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड द्वारा खारिज नहीं किया गया था। सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफ़ी कैशन इंक., (2013) 1 एससीसी 641:(2013) 1 एस. सी. सी. (सी. वी.) 689]।”

21. इस न्यायालय ने अंततः यह अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 8 और 11 में अन्य बातों के साथ-साथ संशोधन लाने का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्राधिकरण के दायरे को कम करना था, जो केवल इस आधार पर मध्यस्थता के संदर्भ से इनकार करना था जब वह प्रथम दृष्टया यह मानता है कि कोई वैध मध्यस्थता समझौता नहीं था। संशोधन के लिए विधायी इरादे को न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करने के लिए माना गया था, और एक बार जब न्यायालय यह मान लेता है कि एक वैध मध्यस्थता समझौता है, तो उसके पास मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि जहां मामला स्वयं गैर-मध्यस्थ है, या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जैसे विशेष कानून द्वारा कवर किया गया है, फिर भी इसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए। एम्मार III (ऊपर) के पैरा 59 में, यह निम्नानुसार कहा गया था:

287

एसएमटी। एम. हेमलाथा देवी और ओआरएस बनाम बी. उदयश्री [सुधांशु धूलिया, जे.] 288

“59. धारा 8 में संशोधन को इतना व्यापक अर्थ और इरादा नहीं दिया जा सकता है कि विशेष विधानों की पूरी व्यवस्था को जलमग्न कर दिया जाए जहां ऐसे विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं थे। कुछ ऐसा जो कानून का इरादा कभी नहीं था, उसे तय किए गए कानून को ओवरराइड करने के लिए साइड विंड के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का निवेदन कि संशोधन के बाद इस न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम में निर्धारित कानून लिमिटेड [राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड वी. एम. मधुसूदन रेड्डी, (2012) 2 एससीसी 506:(2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 908] अब एक अच्छा कानून स्वीकार नहीं किया जा सकता है। “उच्चतम न्यायालय या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद” शब्द केवल उन

उदाहरणों के लिए थे जहां यह निर्धारित किया गया था कि न्यायिक प्राधिकरण धारा 8 के तहत संदर्भ देते समय मध्यस्थता समझौते के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने का हकदार होगा, मध्यस्थता का विषय चाहे दावा जीवित हो या मृत, क्या मध्यस्थता समझौता अमान्य है। धारा 8 में जोड़े गए शब्द किसी अन्य अर्थ के लिए नहीं हो सकते हैं।”

एम्मार III (ऊपर) हालांकि एक चेतावनी के साथ समाप्त होता है, जहां यह उस पक्ष के पास विकल्प छोड़ देता है जिसके पास सार्वजनिक या निजी मंच के बीच चयन करने का विकल्प हो सकता है, वह सचेत रूप से निजी मंचों के लिए जाने का विकल्प चुन सकता है। इसमें कहा गया है:

“63. हालांकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मूर्तियों के तहत प्रदान किए गए अतिरिक्त विशेष उपचार की मांग करने का हकदार है, तो वह अतिरिक्त/विशेष उपचार का विकल्प नहीं चुनता है और वह मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है, तो मध्यस्थता में विवादों को आगे बढ़ाने में कोई बाधा नहीं है। यह केवल वह मामला है जहां विशिष्ट सी/विशेष उपचार प्रदान किए जाते हैं और जिन्हें एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा चुना जाता है कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए हटाने से इनकार कर सकता है।”

22. इस प्रकार, मामले में हमारी सुविचारित राय में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अपने दो विवादित आदेशों में सही दृष्टिकोण अपनाया था, जहां उसने मामले में हस्तक्षेप करने और एक मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार कर दिया था।

एम्मार III (उपर्युक्त) में सत्य है कि इस न्यायालय ने धारा 8 की उप-धारा (1) के दायरे की जांच की थी न कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 11 की उप-धारा 6 ए की। फिर भी, उपरोक्त निर्णय में दिया गया तर्क उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 11 के आवेदन पर समान रूप से लागू होगा। धारा 8 और धारा 11 में शामिल दोनों प्रावधान

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 [अर्थात्, क्रमशः उप-धारा (1) और उप-धारा 6 ए], मध्यस्थता या मध्यस्थ की नियुक्ति के संदर्भ में संबंधित न्यायालयों द्वारा परीक्षा के दायरे को सीमित करता है, जैसा भी मामला हो, और भाषा सामान्य होने के कारण, "किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद" दोनों न्यायालयों के समक्ष एक समान प्रश्न रखता है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रधान सिविल न्यायालय या उपभोक्ता निवारण मंच जैसे न्यायिक प्राधिकरण के पास किसी विवाद की मध्यस्थता के आधार पर धारा 8 के आवेदन को खारिज करने की शक्तियां हो सकती हैं, तो क्या ऐसी शक्तियां उच्च न्यायालयों के पास उपलब्ध नहीं होंगी? एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम. पटेल एंगलिमिटेड 4, इस न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 8 और धारा 11 दोनों पूरक

प्रावधान हैं। विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कार्पोरेशन में संशोधन के बाद के संदर्भ में इस स्थिति को दोहराया गया है।^{5 23} मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत आवेदन, वर्तमान मामले में बनाए रखने योग्य नहीं था, और परिणामस्वरूप हम 19.05.2022 और 25.11.2022 दिनांकित विवादित आदेशों को बरकरार रखते हैं, जो इस स्थिति में थे। हम इस मामले पर आगे कुछ भी कहने से बचते हैं क्योंकि विवाद अभी भी राज्य उपभोक्ता मंच (अपीलीय प्राधिकरण) के समक्ष विचाराधीन है।

24. एतद्द्वारा याचिकाएँ खारिज की जाती हैं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिकाएँ खारिज कर दी गईं।

दिव्या पांडे

4 (2005) 8 एससीसी 618 5 (2021) 2 एससीसी 1